

एक तीनों ओरोंपियों को हियसमें
 ले गये। लिपिरात्रा ओरोंपियों को
 एकलका अम्मं एट्ट के तहत
 मम्मल दर्ज किया गया है। पकड़
 एय चुकोरों की पहचान लकी
 ब्येकर (18 वर्ष), निवारी
 संसलपारा गुंडदेही, संस्कार
 सोनी (23 वर्ष), निवारी कोशल
 निवेधिवाल्ल के पास गुंडदेही
 ओर पटुम भावरी गोस्वामी (24
 वर्ष), निवारी वड्ट क्रमक 04
 गुंडदेही के रूप में हुई है। पुलिस
 ने बताया कि सोशल मीडिया पर
 विधायकों का प्रदर्शन और अश्लील
 भाषा का प्रयोग कानूनन अपराध
 है। ऐसे मामलों में आगे भी सख्त
 कार्रवाई जारी रहेगी।

गांव सशक्त होंगे, तभी साकार होगा विकसित भारत का संकल्प: मंत्री तोखन साहू

‘वार्तालाप’ में वीबी जी-राम-जी अधिनियम 2025 पर हुई चर्चा, ग्रामीण विकास को मिली नई दिशा

बिलासपुर/नवप्रदेश। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय, रायपुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित बिलासपुर में एक दिवसीय क्षेत्रीय मीडिया कारशाला ‘वार्तालाप’ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का मुख्य विषय ‘विकसित भारत-गार्टी रूर रेगनार एंड आर्थोनिक्स मिशन (ग्रामीण)।’ रहा था, जो ग्रामीण भारत के अधिक और समावेशक कायाकल्प की दिशा में केंद्र सरकार की एक युगान्तरणी पहल है।



कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साहू ने कहा कि जी-राम-जी अधिनियम, 2025 केवल एक योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास को ‘विकसित भारत’ के संकल्प से जोड़ने वाली एक आधुनिक रणनीति है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस मिशन की प्रारंभिक ग्रामीण आवश्यकताओं को विचारित करने से मुक्त करने, सीमा तथा हस्तगत सुविधाएं प्रदान करने और ग्राम समाजों को निर्माण लेने हेतु वस्तुनिष्ठ राशि प्रदान करने पर टिकी है। मिशन की प्रारंभिक और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए

दिया गया है। यह मिशन न केवल रोजगार सृजन पर केंद्रित है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे और स्थानीय उत्पादक संस्थितियों के निर्माण के माध्यम से गांव के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक में मुक्ति करने हेतु प्रोत्साहित है। कार्यक्रम के दौरान ‘विकसित भारत जी-राम-जी’ अधिनियम, 2025 के अंतर्गत की गई पहलों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस मिशन को मनसरी अधिनियम में एक युगान्तरणी सुधार बताते हुए साझा किया गया कि यह अब केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप विकास और उत्पादक संस्थितियों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि अब ग्राम पंचायतों को उनके विकास कार्यक्रमों के आधार पर ए. बी. और सी श्रेणियों में विभाजित कर

पीएम मोदी का विकसित भारत 2047 का विजन सराहनीय: साहू

श्री साहू ने बताया कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘विकसित भारत 2047’ का विजन अत्यंत सराहनीय है और हम सभी एकजुट होकर एक विकसित और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। जी-राम-जी अधिनियम के तहत अब गांव परिवारों को उनके विकास कार्यक्रमों के आधार पर ए. बी. और सी श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। ग्रामीण विकास को नई नति देने के लिए अब गांव परिवारों को ‘पीएम मोदी राशि मिशन’ से जोड़ा जा रहा है, जिससे विकसित गांव विकास को साथ मिलकर एकजुट योजना के तहत कार्य का पथ और विश्वास सुनिश्चित होगा। ‘संसाधन लक्ष्य योजना और दूरदर्शिता के समाधान से गांव के अंतर्गत व्यक्ति एक विकास पाहुन है।’

कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर जिला पंचायत की सदस्य प्रदीपका अधिकारी (अध्यक्ष) अनुसूचित सुधार ने अपने संबोधन में कहा ‘विकसित भारत जी-राम-जी मिशन गांवों क्षेत्रों में आर्थिक सुधार और विकास के लिए एक नया का पथ साबित होगा।

जल संधार, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर और जलसंधार परियोजना को प्रारंभित करने से निपटने हेतु कार्य को सम्मिलित किया गया है।

न्यूज़ गैलरी

स्काउट गाइड अग्रवाल विवाद

सांसद अग्रवाल ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

बिलासपुर/नवप्रदेश। स्काउट गाइड अग्रवाल का विवाद गहने लगा है। प्रशासनिक स्तर से यह मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। सांसद बुजुर्गमोहन अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अग्रवाल पर से पदार्थ जाने को असंवैधानिक करार दिया है। बालीयट जिले में 9 से 13 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल रैंजर चुनने को लेकर विवाद गहने लगा है। सांसद बुजुर्गमोहन अग्रवाल ने खुद को भारत स्काउट गाइड की राज्य परिषद का अध्यक्ष बताते हुए आवेदन को स्वीकृत करने की घोषणा कर दी है। जंग्गी को स्वीकृत करने की घोषणा के साथ ही सांसद बुजुर्गमोहन अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। दायर याचिका में सांसद अग्रवाल ने कहा है उनके पद से हटाया जाना असंवैधानिक है। सांसद ने अपने याचिका में इस मामले की सीमा सुनवाई का आग्रह किया है कि वह है। सांसद बुजुर्गमोहन अग्रवाल और स्कूल शिक्षा मंत्री नरेंद्र रायच के बीच स्काउट गाइड के अध्यक्ष पर की दायरवादी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दोनों अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं। सांसद बुजुर्गमोहन अग्रवाल का दावा है कि 10 करोड़ की वित्तीय अविश्वसिता के कारण आवेदन को रद्द कर दिया गया है।

विरोध के बाद पुलिस पहुंची, प्रभावित परिवार पीएम आवास में शिफ्ट 40 से अधिक बेड़ा कब्जा मकानों पर निगम ने चलावाया बुलडोजर

बिलासपुर/नवप्रदेश। शहर में अरपा पर एसईसीएल के डीटा विहार कॉलोनी से सटे बेकाबावा बंसीड मोहल्ले में अतिक्रमण करने की कार्रवाई की गई। नगर निगम अपने ने पुलिस की मौजूदगी में 40 से अधिक बेड़ा कब्जा वाले मकानों को हटा दिया। इस दौरान नागरिकों ने कार्रवाई का विरोध भी किया।



कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध

कार्रवाई शुरू होते ही कुछ लोगों ने अपने घरों को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सामान शिफ्ट करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा, लेकिन जून कमिशनर विभा सिंह, सब डीप्टीनर जगजित सिंह और वहां साहू सहित अन्य अधिकारियों ने इससे इनकार कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमणकारीयों को सितार से अब तक तीन बार नोटिस और कई बार मोहलत दी जा चुकी थी।

था। इस अतिक्रमण के कारण जल और खस खसोड मोहल्ले को खाली करने के लिए निगम अमका वह महीने से तैयारी कर रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में अक्सर जलप्रवाह की स्थिति बन जाती है। बेड़ा कब्जा में खस खसोड मोहल्ले को खाली करने के लिए निगम अमका वह महीने से तैयारी कर रहा था। बारिश पड़ेले 66 डिग्रीसेल्सिड से

सामग्री लेकर उन्हें मकान आवंटित किया गया। इसके बाद उन्हें सामग्री शिफ्ट करने के लिए कहा केसर और कर्मचारी उत्पन्न करार गए। पूरा बंसीड मोहल्ला खाली करने में निगम अपने को दो दिन और लगा उनके घरों में रुकरीय सेंसर प्लॉट लगाते के लिए देश में पहली भूमि में उद्यान, नाला और सड़क चौड़ीकरण का कार्य करने की योजना बनाई है। इस साहू के मृत्युविक्रम अब इसका इस्तेमाल तैयार किया जाएगा। साहू ने जानकारी दी कि 66 परिवारों को मकान खाली करने और उन्हें इमरालीभार स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों में स्थानांतरित करने पर पहले ही सम्मति बन चुकी थी। आज जिन 40 परिवारों को इमरालीभार में शिफ्ट किया गया है, उन्हें मकान आवंटित किए जा चुके हैं। 66 लोगों ने मकान के पंजीकरण के लिए 5 हजार रुपये भी जमा कर दिए हैं।

पहाड़ी कोरवा परिवारों को निःशुल्क रूफटॉप सोलर प्लांट की पहल

■ आवास-बिजली निःशुल्क, योजनाओं के अभिसरण से देश में रक्षा पहला कार्य



बिलासपुर/कोरवा/नवप्रदेश। छात्रसंगठन और छात्रसंगठन स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अत्यंत पिछड़े जनजाति परिवारों को आवास की सुविधा देने के साथ उनके घरों में रूफटॉप सोलर प्लॉट लगाने के लिए देश में पहली बार एक नई पहल की है। इस पहल सरकार द्वारा भी रूफटॉप सोलर प्लॉट स्थापना सहस्रवर्षी दी जा रही है। प्रधानमंत्री जनमानस योजना के अंतर्गत अत्यंत पिछड़े जनजाति के परिवारों को सौर ऊर्जा की सौभाग्य मिल रही है। यह एक ऐसी पहल है जिससे न सिर्फ प्रधानमंत्री सुप्रीम मुक्त बिजली योजना को सार्थक किया गया है

मिशन देने का एक स्थानीय प्रतीक बनाया गया है। छात्रसंगठन में मुख्यमंत्री विमलेश साय ने प्रधानमंत्री सुप्रीम मुक्त बिजली योजना का लाभ वस्तुनिष्ठ जरूरतमंद परिवारों को पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किये हैं। केन्द्र की तंत्र पर राज्य सरकार द्वारा भी रूफटॉप सोलर प्लॉट स्थापना सहस्रवर्षी दी जा रही है। प्रधानमंत्री जनमानस योजना के अंतर्गत अत्यंत पिछड़े जनजाति के परिवारों को सौर ऊर्जा की सौभाग्य मिल रही है। यह एक ऐसी पहल है जिससे न सिर्फ प्रधानमंत्री सुप्रीम मुक्त बिजली योजना को सार्थक किया गया है

हमारे जीवन सार्वजनिक: मंगल राम

योजना के तहत पहाड़ी मंगल राम, गीता बाई, संतोषी बाई, परिषदा, सुभक्त का परिवार बहुत खुश है कि उसे अब निरन्तर बिजली मिलेगी और बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम लोग मजदूर हैं। हमें नहीं पता था कि कैसे लाभ मिलेगा। विद्युत कंपनी के लोगों ने ही आवेदन करने से लेकर हर काम में हमारी मदद की। और मुद्रमंजुषा को एक अलग पहचान दिला दी है।

जनहित की व्यापक सोच: डॉ. रंजित यादव

छत्रीसंगठन स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रंजित यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री विमलेश साय की व्यापक सोच में सब योजनाओं के अभिसरण का मार्ग प्रशस्त किया। परिणाम सामने है कि जहां जहां भी, वहां राह होती है। पहाड़ी कोरवा परिवारों को इस योजना से बहुत लाभ मिलेगा। साहू ही उनके जैसे जीवनशरत वाले अन्य परिवारों को लाभान्वित करने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

बड़ी सोच का नतीजा: भीम सिंह

छत्रीसंगठन स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भीम सिंह ने कहा कि हमारे अध्यक्ष डॉ. रंजित यादव रस्ता निकालना चाहते थे कि अधिकतम जरूरतमंद परिवारों को पीएम सुप्रीम मुक्त बिजली योजना का लाभ कैसे दिलाया जायें। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री जनमानस योजना, परिणाम में समन्वय से यह रस्ता मिल गया और अत्यंत पिछड़े जनजाति के घर शिड आवासीय सोलर पॉवर से जोड़ा कर हमने देश में एक अलग मिशन कायम कर दी है। फिलहाल तो यह एक पायलट प्रोजेक्ट है लेकिन इसकी सफलता हमारे राज्य को नई बलिकें पूरे देश को नया रास्ता दिखाएगी।

एसईसीएल और सत्य साईं ट्रस्ट की साझेदारी से नवा रायपुर में बनेगा हेल्थकेयर स्किल डेवलपमेंट सेंटर

■ 35.04 करोड़ की लागत से स्थापित होगा अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थान



बिलासपुर/नवप्रदेश। छात्रसंगठन के कोल बेकर में स्वास्थ्य सेवाओं और रोगनायक कोल विकास से नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, सत्य साईं ट्रस्ट कोलवेल्लस रिमिडियट (एसईसीएल) ने श्री सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट और सत्य समझौता ज्ञान (एसएओ) पर दिनांक 07 जनवरी 2026 को हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत नवा रायपुर, छात्रसंगठन में 35.04 करोड़ की लागत से एक आधुनिक हेल्थकेयर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह कारपोरेट सोलर रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) के अंतर्गत संचालित होगा। यह संस्थान सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित युवाओं को निःशुल्क और रोगानामोक्त स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यहां नर्सिंग, अल्ट्रासाउंड, मेडिकल डेवेलपमेंट तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एसईसीएल की और से

तमनार की घटना पर हाईकोर्ट नाराज, महाधिवक्ता से मांगी जानकारी

बिलासपुर/नवप्रदेश। तमनार में हुई घटना को लेकर हाईकोर्ट की नाराजी सामने आई है। चीफ जस्टिस की छल्लेन बेंच में इसी तरह के मामले की सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के बीच में चीफ जस्टिस ने तमनार की घटना का उत्प्रेषण करते हुए इस पर चिंता भी व्यक्त किया और नाराजगी भी जताई। यह महाधिवक्ता को तलब कर शस्त्र का जवाब मांगा गया है। अभ्युक्तों को एक मामले को लेकर चीफ जस्टिस रोश सिद्ध के डिवीजन बेंच में सुनवाई हो रही थी। राजधानी रायपुर को एक

की स्थिति बन जाती है। बेड़ा कब्जा में खस खसोड मोहल्ले को खाली करने के लिए निगम अमका वह महीने से तैयारी कर रहा था। बारिश पड़ेले 66 डिग्रीसेल्सिड से



में मुख्य आरोपी का पुलिस से सड़क पर अंडर विरार और फटे बर्नियान में लिफ्टिक पोल्कर जुलूस निकाला था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रोश सिद्ध ने तलबी के साथ उक्त मामले में नाराजगी जताई और शासन की ओर से खड़े अधिवक्ता को कहा कि इस मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता को तलब किया जाए। रायगढ़ जिले के तमनार में जिल्ल इंडस्ट्री के कल ब्रॉकि खदान के आवंटन के खिलाफ ग्रामीण धना प्रदर्शन कर रहे थे।

बेहतर शिक्षा के लिए 250 बच्चों को किया गया सम्मानित

बिलासपुर/नवप्रदेश। छात्रसंगठन राज्य अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा मुखवार को बिलासपुर स्थित प्रधान नारा धवन में अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा प्रथिमा सम्मान समारोह के तहत एक दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और उनके भीतर आत्मविश्वास का संचार करना छात्राओं के दौरान विभिन्न शासकीय और आशा की स्थलों से चयनित लगभग 250 छात्र-छात्राओं की प्रमाण पर और उल्लेख देकर सम्मानित किया गया।

अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह



आयोग के सदस्यों और अतिथियों ने बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें प्रशिक्षण और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर यह भी बताया गया कि अल्पसंख्यक आयोग पिछले दो वर्षों से लगातार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिससे छात्राओं में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी है। समारोह में बड़ी संख्या में

विद्यार्थी और उनके अभिभावक उपस्थित थे। अभिभावकों ने अपने बच्चों की साराहना करते हुए कहा कि ऐसे अवसरों से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और वे पढ़ाई को लेकर अधिक गंभीर होते हैं। वहीं विद्यार्थियों ने भी सम्मान पत्रक लुब्धकता जताई और आगे बढ़ी मेहनत करने का संकल्प लिया। आयोजनकर्ताओं का कहना था कि प्रतिभा सम्मान जैसे कार्यक्रम न केवल बच्चों को शैक्षिक-उत्तम के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उन्हें बेहतर शिक्षा प्राप्त करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी प्रभावी प्रेरणा प्रदान करते हैं।

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अत्यवस्थाओं से किसान परेशान

■ कांग्रेस नेता विजय के नेतृत्व में कलेक्टर को सीधा ज्ञापन

बिलासपुर/नवप्रदेश। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में आ रही गंभीर समस्याओं को लेकर बेलातर विधानसभा क्षेत्र के किसानों का आक्रोश लगावत बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता विजय के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते में तत्काल सुधार की मांग की है। किसानों का कहना है कि नई समय रहते समस्या का समाधान

उपलब्धि

रेलवे पर संरक्षण को बढ़ावा देने व संरचनात्मक सुधार के क्षेत्र में किए उत्तेजनीय कार्य रेल परिचालन को सुदृढ़ बनाने, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं व ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना उद्देश्य



रूप, बिलासपुर में 33 केवी उपकरणों पर, नवा 250 केवीय छिनी स्टेट स्थापित एवं कमिशन किया गया। इसके अतिरिक्त छिनी विद्युत कार्यालय, बिलासपुर में अतिरिक्त 250 केवीय किटोसल मेक

सुनिश्चित की गई। 33 केवी रिसीविंग उपकरणों में 33 केवी के 03 नए कंट्रोल पैन्ल स्थापित किए गए। शाहदोल स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा हेतु 16 मीटर ऊंचाई का 01 नया हाई मास्ट स्थापित किया गया। 2572 पुराने पारंपरिक फंशों के स्थान पर नए ऊर्जा दक्ष कीपलंडरीयों स्थापित किए गए। बिलासपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर कुल 11,027 मीटर पलट्री केवल बिजली का कार्य पूरा किया गया। 400 एम्पियर के 03 नए एलटी पैन्ल तथा 800 एम्पियर के 05 नए एलटी पैन्ल विभिन्न उपकरणों एवं रेलवे अस्पताल में स्थापित किए गए।

सिस्टम में सुधार व यात्री सुविधा विस्तार

यात्रिण एवं रेलवे स्टाफ की सुविधा बढ़ाने हेतु रायगढ़ स्टेशन पर 02 नई लिफ्ट तथा बाबा स्टेशन पर 02 नई लिफ्ट स्थापित एवं कमीशन की गई। मंडल के विभिन्न स्टेशनों के प्रतीक्षागृह, रंगमंच, सुरक्षा गैराला, टी.बी.डी. रुम, टीटी स्टेट रुम एवं पीआरएस कार्यालयों में 19 नई 2 टन क्षमता की एसी मशीनें तथा 02 नई 1.5 टन क्षमता की एसी मशीनें स्थापित की गईं।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना से मछुवारों की बदली आर्थिक स्थिति, लगातार बढ़ते जा रहा उत्पादन

□ किसानों व मछुवारों की बदली आर्थिक तस्वीर, दो वर्षों में बदली मत्स्य क्षेत्र की तस्वीर

□ बड़े पैमाने पर तालाब एवं संवर्धन पोखरों का निर्माण

रायपुर/नवप्रदेश। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के सभी जिलों में मत्स्य क्रांति की मजबूत नींव रखी जा रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों एवं मछुवा परिवारों के जीवन में उल्लेखनीय और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर मत्स्योत्पादन क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है, जिससे आय एवं रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं।

राजनांदगांव जिले में मत्स्य बीज उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 2 नवीन हेक्टेयर का निर्माण किया गया है, जिससे जिला अब मत्स्य बीज



मत्स्य बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर राजनांदगांव जिला

उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगम है। इसके परिणामस्वरूप जिले में मछली बीज उत्पादन में 20 प्रतिशत तथा कुल मत्स्य बीज उत्पादन एवं संवर्धन हेतु

1500 मछुवारों को मिला प्रशिक्षण एवं संसाधन

मछली पालन की आधुनिक तकनीकों को जानकारी हेतु राजनांदगांव जिले के 1900 मछुवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके साथ ही मछुवा परिवारों को मछली बीज, जाल, आइस बॉक्स, मोटर साइकिल एवं फिकअप वाहन जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। किसान ऑनलाइन कार्ड योजना के माध्यम से मछुवारों को सस्ती एवं सुलभ ऋण सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

जिले में 3 प्रखंडों की स्थिति की गई है। इसके अतिरिक्त किसानों की निजी भूमि में 148 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 590.166 लाख रुपये की लागत से नवीन तालाब एवं संवर्धन पोखरों का निर्माण किया गया है।

आधुनिक तकनीकों से बढ़ा मत्स्योत्पादन



किया जा रहा है, जिससे सीमित जल ससाधनों में भी अधिक उत्पादन संभव हो पाया है।

रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि

मत्स्य पालन से जिले में 2500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। योजना के अंतर्गत 11 हजार 471 महिला हितधारियों को निःशुल्क ट्रेडिंग बीमा, 1900 हितधारियों को प्रशिक्षण, 450 हितधारियों को मछली जाल,

आइस बॉक्स एवं मछली बीज प्रदान किया गया है। पिछले दो वर्षों में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के सफल क्रियान्वयन से जिले के मत्स्य क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। किसानों एवं मछुवारों को आय में वृद्धि, रोजगार के नए अवसर और मत्स्य उत्पादन में निरंतर बढ़ोतरी इस योजना की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

धान खरीदी नीति ने बदली किसानों की किस्मत पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान से खुशहाली

खुशहाली का नया दौर, सुव्यवस्थित खरीदी से किसानों को मिल रहा उचित मूल्य



□ किसानों की आर्थिक स्थिति

हुई मजबूत

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ सरकार की धान खरीदी नीति ने किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू की गई यह नीति न केवल पारदर्शी और सुगम है, बल्कि किसानों को उनके पसंदीने की कमाई का पूरा हक दिला रही है। समर्पण मूल्य पर समयबद्ध भुगतान और आधुनिक व्यवस्था ने राज्य के लाखों

ऑनलाइन टोकन और पारदर्शी प्रक्रिया से खतबूंद परेशानियां

राज्य सरकार की पहल से धान खरीदी में क्रांति आ गई है। ऑनलाइन और समिति आधारित टोकन प्रणाली ने लंबी कतारों व अव्यवस्था का अंत कर दिया है। किसानों को अब न तो इंतजार करना पड़ता है और न ही कोई बिचौलिया हस्तक्षेप होता है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से निगरानी में रहती है, जो पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

किसानों की आर्थिक रूप से मजबूत जोधन केंद्र की सफलता इस नीति की किस्मत है, जिससे ग्रामीण अव्यवस्था में नई गति आई है। गोरिल-पेठरा-मरवाही जिले के किसान दो चरणों में कुल 99 डिजिटल उपकरण केंद्र

किसान हित में सरकार की प्रतिबद्धता, कृषि क्षेत्र में बढ़ा विश्वास



मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की यह नीति छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। किसानों को समय पर भुगतान मिलने से वे नई फसल के लिए बेहतर निवेश कर पा रहे हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। राज्य भर के उपार्जन केंद्रों पर सुव्यवस्थित व्यवस्था ने ग्रामीणों का भरोसा जीत लिया है। जोधन केंद्र ने कहा कि सरकार की इस किसान हितैषी नीति से हमारी तस्वीर बदल गई है। अब हम बिना चिंता के खेतों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति राज्य को कृषि प्रधान अव्यवस्था के रूप में मजबूत करवाती। सरकार की यह सहकारक पहल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रही है।

पेड़ में बेचा। जोधन ने खुशी से बताया कि पहले की तुलना में अब खरीदी प्रक्रिया कहीं अधिक बेहतर और आसान हो गई है। समिति के माध्यम से उन्नत कटवर्क बिना किसी झटके के धान बेच पाया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा घोषित 3100 रुपये प्रति डिजिटल की दर और प्रति एकड़ 21 डिजिटल धान खरीदे

की सोमा ने किसानों की चिंताओं को दूर कर दिया। जोधन केंद्र जैसे हजारों किसान अब अपनी उपज को पूरा मूल्य समय पर प्राप्त कर रहे हैं, जिससे उनके परिवारों में खुशहाली रौंद आई है। यह व्यवस्था न केवल आर्थिक लाभ दे रही है, बल्कि किसानों में आत्मविश्वास भी भर रही है।

जनदर्शन में मांगे पूरी होने पर खिले चेहरे ट्राइसिकल, ह्वीलचेयर और श्रवण यंत्र मिले

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान हितधारकों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ कक्षा सम्पादन किया। इस अवसर पर जनसहभागिता दिवसों की बेटी ट्राइसिकल, ह्वीलचेयर एवं श्रवण यंत्र मिले। मुख्यमंत्री साय ने जनदर्शन में आय से आगे भी भारत शाहू को बेटी चर्चित ट्राइसिकल प्रदान किया, साहू ने बताया कि अब उन्हें कहीं आने-जाने के लिए दूसरी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहले किसी के सपना मिलने पर ही वे बाहर जा पते थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती



बी. बेटी ट्राइसिकल मिलने से उनका जीवन अब कहीं आर्थिक सहज हो जा जाएगा। इसी तरह खमराव रायपुर निवासी जीवन

दास मनीकपुरी ने बताया कि उनका घर बचपन से पोलियोग्रस्त है, आज उन्हें बेटी ट्राइसिकल प्रदान की गई। श्री दास ने बताया कि जनदर्शन में उनकी समस्या का तत्काल समाधान हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सहायता से उनकी दैनिक दिनचर्या आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने रायपुर के मोबा निवासी श्री चंदू यादव को ट्राइसिकल और सुशी सुमन साहू को ह्वीलचेयर प्रदान किया। जिससे पाकर दोनों के चेहरे खिल गए। जनदर्शन के दौरान रायपुर निवासी श्री सागर नायक एवं श्री अंशु पटेल को श्रवण यंत्र भी प्रदान किए गए।

पीएम आवास योजना के तहत 40454 आवास निर्माण की मिली स्वीकृति

रायपुर/नवप्रदेश। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण एवं कच्चे मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान आवास बनाने के लिए पात्र हितधारियों को 1 लाख 20 हजार रूपए एवं मनरेगा योजना से 90 मानव दिवस मजदूरी की सहायता दी जाती है। शासन द्वारा जिले में विगत दो वर्षों में 40454 आवास निर्माण की स्वीकृति मिली। वित्तिय वर्ष 2024-25 में 30766 आवास स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें से 23294 आवास पूर्ण कर लिया गया है तथा 7472 आवास प्रगतिरत हैं। इसी प्रकल्प अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 9688 आवास स्वीकृत किये गये हैं। जिसमें से 7026 हितधारियों को प्रथम किस्त प्रदाय किया गया है। प्रथम



आवास योजना-ग्रामीण में स्वीकृत हितधारियों के आवासों का समग्र-समय पर भूखे पुजन तथा पूर्ण हुए आवासों का हितधारियों के उपस्थिति में गृह प्रवेश कार्यक्रम का आगोजन कर रहा है।

जिले में तत्काल द्वा द्वार एक दिवसीय अधिवेशन का आगोजन करते हुए स्वीकृत हितधारियों को अग्रिम अवासी को प्रारंभ करने, निर्माणगोता आवास को समन-सीमा में पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

बिहान योजना से बदल रही जिंदगी, लखपति दीदी बनकर आगे बढ़ रहीं जिले की महिलाएं

रायपुर/नवप्रदेश। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की मदद से कबीरधाम जिले की महिलाएँ आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। वे अब केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि काम करके परिवार की आमदनी भी बढ़ रही है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रही बिहान योजना ने महिलाओं के जीवन में एक नई रोशनी लाई है। इसी योजना से जुड़कर कई महिलाएँ आज लखपति दीदी बन चुकी हैं। इनका का सक्षमता सता-प्रतिशत पंजीयन पूर्ण करने वाला जिला बना गया है। जिले में तत्काल द्वा द्वार एक दिवसीय अधिवेशन का आगोजन करते हुए स्वीकृत हितधारियों को अग्रिम अवासी को प्रारंभ करने, निर्माणगोता आवास को समन-सीमा में पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।



मिली। इसके बाद, उन्होंने मछली पालन को अपने रोजगार का सफर बनाया। एनआरएलएम के सहयोग से समुदायिक तालाब में वैक्यूम तरीके से मछली पालन शुरू किया गया। सही देखरेख और समय पर भोजन देने से मछली उत्पादन बढ़ा। इससे मछली बेचकर अब निर्वाह और अच्छी आमदनी होने

लगी। अब वे घर के खर्च आसानी से चल पा रही हैं और बचत भी कर पा रही हैं। आज वे महिलाएँ लखपति दीदी बनकर जिले की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। मछली पालन से मिली आय ने उनकी आर्थिक स्थिति भी नहीं, बल्कि आजीवनिक और समाज में सम्मान भी बढ़ाया है।

नाली में गंदगी डालने पर नैवेद्य फैक्ट्री पर 10 हजार का जुर्माना

गुजराती मिशन भंडार को एसटीपी लगाने का नोटिस

रायपुर/नवप्रदेश। रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग ने स्वच्छता से जुड़े जनसहभागिता पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो खाद्य प्रतिष्ठानों के शिफारस कर कचरा संग्रहण के लिए नोटिस जारी किया। इस पर खाद्य दुकान संचालक को भिनी एसटीपी निर्माण करने का नोटिस जारी किया गया और निर्माण के अंशपूर्ण पर 5 हजार रुपये का ई-न्यूनन वसूला गया।

फैक्ट्री संचालक पर तत्काल 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था स्वच्छता व्यवस्था तत्काल सुधारने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किया गया। इसी तरह जोन 4 क्षेत्र अंतर्गत गुजराती मिशन भंडार के आंचक निरीक्षण के दौरान वहां एसटीपी (सीवज ट्रीटमेंट प्लांट) नहीं पाया गया। इस पर खाद्य दुकान संचालक को भिनी एसटीपी निर्माण करने का नोटिस जारी किया गया और निर्माण के अंशपूर्ण पर 5 हजार रुपये का ई-न्यूनन वसूला गया।

कार्रवाई के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी सीएच चंदनकर एवं गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य विभाग के स्वच्छता निरीक्षक निरंजना तिवारी उपस्थित रहे।

आयुष्मान कार्ड एवं आयुष्मान वय वंदना पंजीयन में प्रदेश में राजनांदगांव प्रथम

□ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के इलाज के लिए सुरक्षा कवच

रायपुर/नवप्रदेश। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं एवं सुविधाओं के अंशपूर्ण हेतु निरंतर और प्रभावी कार्य किया जा रहा है। शासन की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी क्रम में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड एवं आयुष्मान वय वंदना कार्ड पंजीयन में राजनांदगांव जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के सभी पात्र हितधारियों के घर-घर पहुंचकर आयुष्मान वय वंदना



वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त निःशुल्क उपचार लाभ

आयुष्मान वय वंदना कार्ड के अंतर्गत घर वरिष्ठ नागरिकों को शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त निःशुल्क उपचार प्रदान किए जाने का प्राधान्य है। इससे बुजुर्गों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। सभी पात्र हितधारियों के घर-घर पहुंचकर आयुष्मान वय वंदना

आयुष्मान कार्ड पंजीयन में भी प्रदेश में अग्रणी

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत जिले में आयुष्मान कार्ड पंजीयन का लक्ष्य 9 लाख 52 हजार 546 के विरुद्ध 9 लाख 37 हजार 461 हितधारियों का पंजीयन किया गया है, जो कि 98.42 प्रतिशत उपलब्धि है। इस उपलब्धि के साथ आयुष्मान कार्ड पंजीयन में भी राजनांदगांव जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।

कार्ड पंजीयन का कार्य पूर्ण किया गया है। इस अधिवेशन के माध्यम से कोई भी पात्र हितधारिता योजना के लाभ से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया गया।

आयुष्मान वय वंदना कार्ड में शत-प्रतिशत से अधिक उपलब्धि

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत जिले में आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 100.20 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त की गई है। इसके साथ ही राजनांदगांव जिला राज्य का सर्वप्रथम शत-प्रतिशत पंजीयन पूर्ण करने वाला जिला बना गया है। जिले में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के 25 हजार 138 पात्र वरिष्ठ नागरिकों में से 25 हजार 88 हितधारियों का पंजीयन किया गया है।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षा कवच

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क, कैशलेस एवं पेंसिलेस उपचार सामाजिक कल्याण का रास्ता है। यह योजना शासन की एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा है, जो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है।



न्यू गैलरी

राम मंदिर में अध्यक्षता छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन



रायपुर/नवप्रदेश। यूको बैंक की मिड कॉर्पोरेट शाखा द्वारा बैंक के 84वें स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत श्री राम मंदिर में अध्यक्षता छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छात्रों को मिश्रित एवं रेस्तरां शास्त्री का विवरण दिया गया तथा समान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने उत्कृष्टप्रदर्शन भाग लिया। कार्यक्रम में सहायक महाप्रबंधक श्री सतीश कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक श्री सौरभ प्रदीप प्रकाश एवं श्री सत्यवीर पाणिग्राही, आचार्य श्री दामोदर कुमार द्विवेदी तथा श्री चंद्रप्रकाश जी उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और समर्पण, सेवाओं एवं समाज के प्रति दायित्व के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने इस पहल के लिए बैंक प्रबंधन के प्रति आभार व्यक्त किया।

समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी करने वाला प्रदेश का पहला जिला बना राजनांदगांव

राजनांदगांव/नवप्रदेश। 7 जनवरी की स्थिति में पूरे राज्य से केवल राजनांदगांव जिला समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदी करने हुए प्रदेश में पहला जिला बनने का गौरव प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री अद्वैता आर्य संरक्षण अभियान के तहत समर्थन मूल्य पर खरीफ में सोयाबीन, अरहर, उड़द तथा मूंग फलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए जिले में इस प्रकार के 15 उपजों के केंद्र चिह्नित किए गए हैं। साथ ही समस्त उपज कृषक उपबन्धक संगठन सहकारी समितियों को उपजों के केंद्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा नफेद के माध्यम से जिले में खरीफ-दहन विरोध फसलों की खरीदी जा रही है। जिसके लिए समर्थन मूल्य पहले ही जारी किया जा चुका है। जिसके अनुसार सोयाबीन 5328 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग 8768 रु, उड़द 7800 रु, अरहर 8000 रु प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। साथ ही उपजों में सोया भी निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार सोयाबीन 5 क्विंटल प्रति एकड़ तथा उड़द, अरहर एवं मूंग प्रति एकड़ प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है।

स्टेशनरी दुकान में नशे के लिए बेचा जा रहा था क्लाइडनर

राजनांदगांव/नवप्रदेश। स्टेशनरी दुकान संचालक द्वारा नशे के उद्देश्य से नकारात्मक वस्तुओं को नशे के उद्देश्य से डायलॉग एवं क्लाइडनर बेचे जा रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने संबंधित दुकान संचालक के खिलाफ प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की है। कोठावली पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना कोठावली क्षेत्र अंतर्गत एक स्टेशनरी दुकान द्वारा नकारात्मक वस्तुओं को नशे के उद्देश्य से डायलॉग एवं क्लाइडनर बेचे जाने की जानकारी प्राप्त हुई। सूचना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना कोठावली पुलिस एवं सहकार टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा मौके पर दबिश देकर दुकानदार को नकारात्मक वस्तुएं एवं डायलॉग एवं क्लाइडनर बेचे हुए गैर हथौथे पकड़ा गया। उक्त प्रकरण में प्रेमलाल निवासी निवासी इंदौरपुर, संचालक देवीराम जलाल स्टोर के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई की गई है। जिला पुलिस राजनांदगांव अमानज को यह स्पष्ट रूप से अवगत कराती है कि नकारात्मक को किसी भी प्रकार के गोपनीय अथवा दुरुपयोग योग्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निजी मोबाइल नशे से टीसर में उपस्थिति देने का निर्णय अव्यवहारिक

गडौड़/गडौड़ा/नवप्रदेश। छात्रीसंगठन टीसर एसएमएसएन ने शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति कोकेसए एवं माध्यम से करने के निर्णय को अव्यवहारिक बताया है। छात्रीसंगठन टीसर एसएमएसएन जिला के टीसर में की के जिला अध्यक्ष संजय सिंह रायपुर, वरिष्ठ अध्यक्ष योगेश्वर राय, वरिष्ठ अध्यक्ष सुखदेव बनवाल जिला ने राज्य सरकार के निर्णय पर आक्षेप दर्ज करते हुए कहा कि उक्त एवं में मेटा द्वारा निर्धारित शर्तों प्रेमलाल, मोबाइल नशे पर उक्त एवं कार्य करेगा। शिक्षकों को निजी जानकारी संबंधित सेवा दान कंपनी के पास होने से बहुत से शिक्षकों के साथ विगत दिल में बहुत से प्रश्न उत्पन्न हुए हैं जिसमें शिक्षकों के खाते से फनी तरीके से पैसा ट्रांसफर हो गया है। शासन का यह निर्णय अव्यवहारिक है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि छ ग ग शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व मुख्यामंत्रि डॉ। रामन सिंह के कार्यकाल में प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में बायोमेट्रिक मशीन का विवरण दिया गया था। उक्त बायोमेट्रिक को अपडेट कर प्रत्येक स्कूल स्तर में सरलता से स्थापित कर स्कूल से संबंधित समस्या जानकारी ऑनलाइन आदाना एवं उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सकता है। शासन इस ओर पहल करे।

नवजात की मौत का मामला, 10 दिन बाद भी नहीं मिली जांच रिपोर्ट

बिलासपुर/नवप्रदेश। अगोले अस्पताल में प्रसव पाँड़ना से लायावली और नवजात की मौत का मामला अवगत अनुसूचित है। घटना को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सीएमएसएन के द्वारा गजित टीम की जांच रिपोर्ट नहीं आ सकी है। बताया जा रहा है कि जांच कलेक्टर के निदेश पर की जानी है, लेकिन इसके बाद भी टीम ने जेस रिपोर्ट अवकाश पेश नहीं की है। ऐसे में टीम के जांच करने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। राअसल 23-24 की दरमियाँ को निवेदन मात्र निवासी पीठ अग्रवाल को प्रसव के लिए हुई रिपोर्टों के कारण नवजात की मौत हो गई थी। मामले में अगोले प्रबंधन पर लायावली का आरोप लगा था और मामले का अपराध प्रकट नहीं हुआ था। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएसएन को टीम बनकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीएमएसएन डॉ. शुभा गोकुल ने 4 सदस्यीय टीम गजित की है लेकिन 10 दिन बाद भी टीम की जांच अंश में अटकी हुई है।

स्वातंत्र्यधारी, प्रकाशक एवं प्रमुख संपादक राधाशंकर शर्मा, शेषा नंदा 74, सेक्टर-जी, उत्तर इंदरप्रदेश परिया परिया, से मुंबई कर तृतीय तल, सुगर मार्केट कोमलेश्वर, राजा खुशाल सिंह स्टडीयम के सामने अग्रवाल कोक, बिलासपुर से प्रकाशित, RNI NO.CHHHIN/2015/62431, संपादक-वन्दनशेखर (पीआरबी एड के तहत खबरों के लिए उत्तरदायी), स्वायत्त संपादक-शिक्षण सिंह ठाकुर, फोन नंबर : 07752-468654, navpradeshbhaspur01@gmail.com

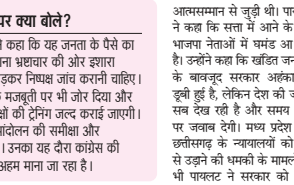
कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, बोले- घमंड में डूबी भाजपा ने कमजोर की मनरेगा, पंचायतों से छीने अधिकार



रायपुर/नवप्रदेश। कांग्रेस के छात्रीसंगठन प्रभारी सचिन पायलट शुक्रवार को एक दिवसीय दौर पर रायपुर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पायलट ने मनरेगा योजना को 'व्यवस्थित तरीके से कमजोर और खत्म करने' का आरोप लगाते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण गरीबों के लिए सुरुआत कचव थी, जिसे भाजपा सरकार ने धीरे-धीरे निष्क्रिय कर दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिलने की गारंटी थी, लेकिन आज हलात ऐसे बना दिए गए हैं कि यह



योजना सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले मनरेगा की पूरी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब व्यवस्था को भी कमजोर कर दिया गया है। इससे गरीबों के रोजगार के अधिकार पर सीधा हमला हुआ है।



पायलट ने कहा कि पहले मनरेगा के तहत कामों का चयन ग्राम पंचायतें करती थीं, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार रोजगार सुनिश्चित होता था। अब योजना को पूरी तरह केंद्रीकृत कर दिया गया है और पंच पर भी केंद्र का नियंत्रण हो गया है। इससे



पंचायतें बेवस हो गई हैं और उनकी भूमिका केवल औपचारिक रह गई है।

भाजपा से पूछे सवाल: कांग्रेस प्रभारी ने भाजपा से सवाल करते हुए कहा कि अगर सरकार को मनरेगा में सुधार करना था तो मनदूरी दर बढ़ाई जाती, काम के

दिन बढ़ाए जाते, लेकिन भाजपा ने तो योजना को ही खत्म करने का रास्ता चुना। उन्होंने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी इस योजना की मूल भावना और आत्मा को ही बदल दिया गया है। यह योजना सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि गरीबों की गरिमा और

नवप्रदेश में अम्बेडकर अस्पताल का नव कीर्तिमान

वाल्त्व प्रत्यारोपण के दौरान बंद हुई हृदय की नसों, स्टेंट से 'चिमनी' बनाकर बचाई मरीज की जान

■ कांड़ोलोनी विभागाध्यक्ष डॉ. श्रीवास्तव एवं टीम ने अल्ट्राथिन (अत्यंत पतले) हिलोवरी सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए स्टेंट लगाकर बचाई 'चिमनी' संरचना



रायपुर/नवप्रदेश। पं. नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के एडवांस्ड कांड़ोलोनी इंटरव्यूट ने नवप्रदेश 2026 की शुरुआत एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ की है। पं. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो. डॉ. विवेक चौधरी ने बताया कि वर्ष 2025 में कांड़ोलोनी विभाग द्वारा 2600 से अधिक जटिल हृदय प्रक्रियाएँ सफलतापूर्वक की गईं। वर्ष 2009

में मात्र 41 मामलों से शुरू हुआ चिकित्सा महाविद्यालय एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के एडवांस्ड कांड़ोलोनी इंटरव्यूट ने नवप्रदेश 2026 की शुरुआत एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ की है। पं. जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो. डॉ. विवेक चौधरी ने बताया कि वर्ष 2025 में कांड़ोलोनी विभाग द्वारा 2600 से अधिक जटिल हृदय प्रक्रियाएँ सफलतापूर्वक की गईं। वर्ष 2009

धमनियाँ वाल्व के काफी समीप और एडवांस्ड प्रक्रियाएँ के दौरान दोनों धमनियों के बंद होने का गंभीर खतरा था। इस जटिलता से निपटने के लिए विशेषज्ञों ने दोनों कोरोनरी धमनियों में स्टेंट डालकर उनके और वाल्व के बीच 'चिमनी' संरचना तैयार की।

प्रक्रिया के अंतिम चरण में वाल्व डिलीवरी के दौरान बाएं पं. की नस के माध्यम से वाल्व प्रत्यारोपण का निर्णय लिया गया। प्रक्रिया की तैयारी एक माह पूर्व विशेष सीटी स्कैन विश्लेषण एवं मुख्यमंत्रि विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत वित्तीय सुविधा के साथ शुरू हुई। जांच में यह भी पाया गया कि मरीज को पर की नसें पतली एवं कैल्शियम सिस्टम को हृदय तक पहुँचाने अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। साथ ही, जमजम संरचनात्मक विरसिले के कारण हृदय की कोरोनरी

30 वर्ष तक के विचाराधीन बंदियों को स्ट्रीट फूड बनाने का प्रशिक्षण

■ छात्रीसंगठन से दूर बंदियों को अपराध से दृढ़ करने नहीं पड़ेगा, जल्द होगी लागू

रोजगार देना उद्देश्य

रायपुर/नवप्रदेश। छात्रीसंगठन में युवा बंदियों को अपराध की दुनिया से दूर कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जेल मुख्यालय ने एक नई योजना तैयार की है। इस योजना के तहत प्रदेश की जेलों में बंद 30 वर्ष तक की आयु के विचाराधीन बंदियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। खास तौर पर कम लागत में शुरू होने वाले स्ट्रीट फूड व्यवसाय के लिए उन्हें मोमोज, चाउमीन, फकोड़े जैसे फास्ट फूड्स, टैकवर करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। योजना को जल्द ही औपचारिक

रूप से लागू कर पूरे प्रदेश की जेलों में विस्तार किया जाएगा। जेलों के अनुसार, इस योजना की अन्तर्भावित शुरूआत रायपुर जेल से हो चुकी है। स्ट्रीट फूड का व्यवसाय कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है और इसका प्रशिक्षण 15 दिन से एक महीने के भीतर दिया जा सकता है। इसी कारण ऐसे विचाराधीन बंदियों को योजना में शामिल किया गया है, जो तीन-चार महीने में जमानत पर रिहा हो जाते हैं। रायपुर सभाग की जेलों में ही लाभांश दो हजार युवा विचाराधीन बंदी हैं, जिनमें 20 प्रतिशत में करीब पांच हजार बंदियों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

छाणों के बावजूद नहीं थम रहा नकली पनीर का कारोबार

केएलपी डेयरी से 1700 किलो नकली पनीर जब्त, कीमत करीब 4.76 लाख

रायपुर/नवप्रदेश। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की सख्ती के बावजूद राजधानी में नकली पनीर का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कारोबारी शहर के आउटर क्षेत्रों में गोदाम बनाकर बेच्छेक नकली पनीर तैयार कर रहे हैं और इसे शहर में खुलेआम खपाया जा रहा है। बुधवार को एफडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाठगांव स्थित एक गोदाम में छापा मारकर 1700 किलो नकली पनीर जब्त किया है। बाजार में इसकी कीमत करीब 4.76 लाख रुपये अंकी गई है।

लगातार जारी है कार्रवाई

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का दावा है कि नकली और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2025 में जिले की बड़ी दुकानों और डेयरीयों में जांच कर मिलावटी मिठाई, पनीर और खाद्य पदार्थों में सख्त कार्रवाई की गई। पिछले एक साल में 35 रसमों से पनीर के रीपल किए गए, जिनमें से अमानक पाए जाने पर करीब 9700 किलोग्राम पनालांग पनीर, पनीर और खाद्य जवात कर नष्ट किया गया।

केएलपी डेयरी एवं मिर्क प्रोडक्ट में बड़ी मात्रा में नकली पनीर बनाया जा रहा है। प्रशासन के आधार पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के टीम मौके पर पहुंची और जांच की। जांचकर्ता के अनुसार, विभाग को सूचना मिली थी कि बार्ड क्रमिक 64 भाठगांव क्षेत्र में स्थित

बीजापुर में जिला स्तरीय अधिकारियों से निवद नेल्ल नार योजना की ती जानकारी

नए ऊर्जा और नई रणनीति के साथ बीजापुर के विकास में जुटें अधिकारी: शर्मा



रायपुर/नवप्रदेश। छात्रीसंगठन शासन के उम्मेदवारों और गुमनामी विचार शर्मा बीजापुर के अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान बुधवार को जिला कार्यालय सभागृह में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ निवद नेल्ल नार योजना-तन्त्रित संघालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभागवार योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए कहा कि केंद्रीय गुमनामी श्री अमित शाह के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक समास माओवाद का पूरी तरह उन्मूलन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद विकास क्षेत्र में शांति, सुख और न्याय का नया अध्याय शुरू होगा। उम्मेदवारों की शर्मा ने कहा



कि माओवाद के समाप्त उन्मूलन के बाद लोगों में विश्वास जगाना और विकास कार्यों में तीव्रता लाना आवश्यक होगा। अब समय बहुत कम है, इसलिए शासन की सभी महाविकास योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन नई उज्ज्वल, नई रणनीति और जनकल्याण की भावना के साथ सुनिश्चित किया जाना। उन्होंने

वीकें तक शासन की योजनाएँ सुगमता से पहुंचेंगी, जिसमें जिला, विकासखण्ड और मैदान समले के अधिकारी-कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उम्मेदवारों ने बताया कि माओवाद मुक्त प्रान्त पंचायतों को विचार परियोजना के तहत 'इन्कव पंचायत' के रूप में एक करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सहायता

दी जाएगी। इसके साथ ही शासन की महाविकासी 'निवद नेल्ल नार' योजना के अंतर्गत जिले के 201 गांवों को शामिल किया गया है, जहां शासकीय योजनाओं की शत-प्रतिशत संतुष्टता और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया जा रहा है। बैठक में एडीजी नवसल ऑपरेशन श्री विकेनरन्ट सिन्हा ने कहा कि बीजापुर में अब शांति और सुख की स्थिति सुदृढ़ हो रही है, जिससे शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पहले की तुलना में अधिक सुगमता आई है। उन्होंने कहा कि पहले और आज के बीजापुर में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है।

पंचायत विभाग के सचिव श्री भीम सिंह ने बताया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का निराकरण लगातार किया जा रहा है और बरकरार शासकीय विकास शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। कलेक्टर श्री सलित मिश्रा ने उम्मेदवारों की विचार शर्मा के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए बीजापुर के समग्र विकास के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आश्वासन दिया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जयंती देवांगन, बरकरा कमिशनर श्री डोमन सिंह, आईजी श्री सुरेंद्रनाथ जी, संचालक श्री अधिनी देवांगन, पुलिस अधीक्षक डॉ. विनोद यादव, एडिएसपी पंचायत सईओ श्रीमती नाना चौधरी सहित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।